भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1481

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र हेतु औद्योगिक योजनाएं

1481. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): भारत सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से उपयुक्त नीतिगत कार्यकलापों द्वारा राज्यों में समग्र औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार की पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, हिमालयी राज्यों/जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षदीप के अलावा कोई राज्य विशिष्ट औद्योगिक विकास योजना नहीं है। हालाँकि, डीपीआईआईटी ने महाराष्ट्र सहित देश में औद्योगिक विकास के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

स्टार्ट-अप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण करना है। जनवरी 2016 में एक 19-सूत्रीय स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना शुरू की गई, जिसने भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए एक मजबूत, अनुकूल और विकास-उन्मुख वातावरण बनाने के लिए कई नीतिगत पहलों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।

21.07.2021 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, डीपीआईआईटी द्वारा 9864 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र में इन स्टार्ट अप्स द्वारा 1,10,510 रोजगार की सूचना दी गई।

औद्योगिक कॉरीडोर:

भारत सरकार ने औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में 3 औद्योगिक नोड्स का विकास शुरू किया है, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत नामतः शेंद्रा – बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), औरंगाबाद के पास, दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए),

जिला रायगढ़, और बेंगलुरु –मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (बीएमआईसी) के तहत सतारा। ये तीनों नोड्स कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

'भारतीय फुटवेयर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम':

आईएफ़एलएडीपी' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र के लिए विशिष्ट पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश को सुविधाजनक बनाना, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है। यह योजना 31.03.2021 तक कार्यान्वित की गई है। महाराष्ट्र राज्य में, आईएफ़एलएडीपी के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

- 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में 11 इकाइयों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 3.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जिसका वर्ष–वार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	**इकाइयों की संख्या**	**वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)**
2017-18	1	0.16
2018-19	1	0.09
2019-20	4	0.78
2020-21	5	2.20

- एलआईडीसीओएम द्वारा रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एमएफएलएसी की स्थापना के लिए डीपीआईआईटी के 49.50 करोड़ रुपये के हिस्से सहित 99 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का एक परियोजना प्रस्ताव दिनांक 17.09.2019 को आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 15वीं बैठक में 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया गया।

संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

भारत सरकार द्वारा, एमआईआईयूएस की योजना के तहत 89.82 करोड़ रुपये की लागत से मराठवाड़ा ऑटोमोबाइल क्लस्टर, औरंगाबाद और कोल्हापुर फाउंड्री क्लस्टर का उन्नयन कार्य दिनांक 31.03.2016 को पूरा किया गया है।

*****